

DAILY **CURRENT AFFAIRS**

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 06-06-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 06 June, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 Syllabus : GS 2 : Indian Polity and Constitution	परिसीमन से दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का समाधान होगा: केंद्र
Page 02 Syllabus : Prelims Fact	तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य को अधिसूचित किया
Page 06 Syllabus : GS 2 : International Relations	जयशंकर ने भारत-मध्य एशिया संबंधों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया
Page 07 Syllabus : GS 2 and 3 : Social Justice : Issues relating to health and Science and Technology	कोविड-19 टीकों का जायजा लिया जा रहा है
Page 08 Syllabus : GS 1 : Indian Society	देरी में अन्याय: जनगणना की घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन देरी अन्यायपूर्ण है
Page 08 : Editorial Analysis: Syllabus : GS 2 : International Relations	यूरोसेंट्रिक रीसेट, भारत के लिए एक प्रवेश द्वार

Page 01 : GS 2 : Indian Polity and Constitution

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने स्पष्ट किया है कि परिसीमन की प्रक्रिया - जो 2027 की जनगणना के बाद शुरू होने की संभावना है - दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करेगी। यह तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन जैसे नेताओं की आलोचनाओं के बीच आया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि विलंबित जनगणना बेहतर जनसंख्या नियंत्रण वाले राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम करने के लिए राजनीति से प्रेरित है।

Delimitation will address concerns of southern States: Centre

Vijaita Singh
NEW DELHI

The delimitation exercise will take care of the concerns expressed by southern States, and discussions will be held with all stakeholders at the appropriate time, the Union Ministry of Home Affairs (MHA) said on Thursday.

In a post on X, a day after it announced that the Census exercise will be concluded by March 1, 2027, the Ministry said that Home Minister Amit Shah has "clarified on many occasions that in delimitation exercise, concerns of southern states will be taken care of and discussed with all concerned at an appropriate time".

'Questionable timing'
On Wednesday, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin had questioned the timing of the Census, saying that the Bharatiya Janata Party (BJP) had deliberately delayed the exercise to 2027, "making their plan clear to reduce Tamil Nadu's Parliamentary representation".

The southern States have been opposing the population-based criteria for the redrawing of constituencies, which was last done on the basis of 1971 Census data.

As per constitutional norms, the first Census held after 2026 can be used as the basis to redraw Lok Sabha constituencies.

In a series of posts on X, the MHA added that the Census was originally planned to be conducted in 2021. "However, due to outbreak of COVID-19 pandemic across the country, the Census work was postponed," it said.

'QUICKER DATA'
» PAGE 6

मुख्य संवैधानिक और शासन संबंधी मुद्दे

• परिसीमन और इसका आधार:

- परिसीमन का तात्पर्य जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से बनाना है। संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए परिसीमन नवीनतम जनगणना पर आधारित है। हालांकि, 42वें संविधान संशोधन (1976) ने 2001 की जनगणना के बाद तक परिसीमन को रोक दिया था और बाद में 84वें संशोधन अधिनियम (2001) द्वारा इस रोक को 2026 के बाद पहली जनगणना तक बढ़ा दिया गया।

• दक्षिणी राज्यों की चिंताएँ:

- तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय सफलता हासिल की है। यदि भविष्य में परिसीमन पूरी तरह से जनसंख्या पर आधारित होता है, तो इन राज्यों को संसदीय सीटें खोने का जोखिम है, जबकि उच्च प्रजनन दर वाले राज्य (मुख्य रूप से उत्तर में) अधिक सीटें हासिल कर सकते हैं। इसे परिवार नियोजन और शासन में अच्छे प्रदर्शन को दंडित करने के रूप में देखा जाता है।

• केंद्र की प्रतिक्रिया:

- गृह मंत्रालय ने आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया है, जिसमें कहा गया है कि दक्षिणी राज्यों की चिंताओं पर विचार किया जाएगा और परामर्श प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। हालांकि, अभी तक इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है कि क्या समानता (जनसंख्या के आधार पर) और दक्षता (शासन प्रदर्शन के आधार पर) दोनों को संतुलित करने वाला कोई फॉर्मूला अपनाया जाएगा।

जनगणना का समय और राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ:

- जनगणना, जिसे मूल रूप से 2021 के लिए नियोजित किया गया था, को COVID-19 का हवाला देते हुए 2027 तक के लिए टाल दिया गया है। आलोचकों का तर्क है कि देरी

राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करती है, जनगणना को परिसीमन से ठीक पहले संरेखित करना, संभावित रूप से 2029 के आम चुनावों से पहले चुनावी गतिशीलता को फिर से आकार देना।

नैतिक और संघवाद आयाम

- समानता बनाम न्याय: क्या जनसंख्या नियंत्रण में सफल होने वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व के साथ दंडित किया जाना चाहिए?
- संघीय चिंताएँ: एक विशुद्ध रूप से जनसांख्यिकीय परिसीमन क्षेत्रीय असंतुलन को गहरा कर सकता है और सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर कर सकता है।
- पारदर्शिता और विश्वास: स्पष्ट रोडमैप के बिना जनगणना में देरी संस्थागत विश्वसनीयता को खत्म कर सकती है और राजनीतिक अविश्वास को बढ़ावा दे सकती है।

आगे का रास्ता

- बहुआयामी मानदंड: अकेले जनसंख्या के बजाय, प्रतिनिधित्व आवंटन में एचडीआई, बुनियादी ढाँचा और राजकोषीय अनुशासन जैसे अन्य संकेतकों पर विचार किया जा सकता है।
- आम सहमति बनाना: केंद्र को सभी राज्यों, विशेषकर उन राज्यों के साथ व्यापक परामर्श सुनिश्चित करना चाहिए जो इस पर गहरी आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं।
- संसदीय बहस: परिसीमन के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली पर संसद में खुली चर्चा से वैधता में सुधार हो सकता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: आगामी परिसीमन अभ्यास ने क्षेत्रीय असंतुलन और संघीय समानता के बारे में चिंताएँ पैदा कर दी हैं। 2026 के बाद जनसंख्या-आधारित परिसीमन के उपयोग के संवैधानिक, राजनीतिक और नैतिक आयामों की आलोचनात्मक जाँच करें। (250 words)

विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर, तमिलनाडु सरकार ने रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की घोषणा की। 524.7 हेक्टेयर में फैला यह अभयारण्य मन्नार की खाड़ी के बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जो एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र और प्रवासी पक्षी हॉटस्पॉट है।

Tamil Nadu government notifies greater flamingo sanctuary at Dhanushkodi

It spans over 500 hectares and is part of the Gulf of Mannar Biosphere Reserve; the move aims at preserving a critical stopover point along the Central Asian Flyway for migratory wetland birds

The Hindu Bureau
CHENNAI

The Tamil Nadu government has officially declared a greater flamingo sanctuary at Dhanushkodi in Ramanathapuram district.

Chief Minister M.K. Stalin inaugurated the sanctuary via video conferencing at an event organised by the Departments of Environment, Climate Change and Forests in Chennai on Thursday to celebrate World Environment Day.

Thangam Thennarasu, holding additional charge as Minister for Environment; R.S. Rajakannapan, Minister for Forests; and Supriya Sahu, Additional Chief Secretary to Departments of Environment, Climate Change, and Forests, participated in the event.

Rich biodiversity

The move aims to preserve a critical stopover point along the Central Asian Flyway for thousands of migratory wetland birds.

The sanctuary spans 524.7 hectares and encompasses both revenue and forest lands within Ra-



Safe zone: Flamingos in Dhanushkodi, Ramanathapuram district. As per the latest bird survey, Dhanushkodi region has over 10,700 wetland birds, representing 128 species. L. BALACHANDAR

meshwaram taluk.

The designated area, part of the ecologically sensitive Gulf of Mannar Biosphere Reserve, is home to a variety of ecosystems, including mangroves, sand dunes, mudflats, and marshes.

These unique features support a rich biodiversity, from migratory birds and marine life to nesting sea turtles.

A Government Order (G.O.) issued on June 4, by Ms. Sahu, noted that ac-

cording to the recent 2023-2024 Wetland Bird Survey, the Dhanushkodi region recorded over 10,700 wetland birds, representing 128 species, including herons, egrets, sandpipers, and both greater and lesser flamingos.

Ecologically crucial

Mangrove species such as *Avicennia* and *Rhizophora* dominate the Dhanushkodi lagoon, providing essential breeding grounds and natural defenses against

coastal erosion. The sanctuary status is expected to encourage responsible ecotourism, generate local employment, and raise public awareness about wetland conservation, the G.O. said.

T.M. Anbarasan, Minister for Micro, Small and Medium Enterprises, Srinivas Reddy, Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force), Rakesh Kumar Dogra, Chief Wildlife Warden, also participated.

इस कदम का महत्व

- **जैव विविधता संरक्षण:**

- यह अभयारण्य पारिस्थितिकी तंत्रों के समृद्ध समूह की रक्षा करता है - मैंग्रोव, रेत के टीले, कीचड़, दलदल - जो बड़े और छोटे फ्लेमिंगो सहित आर्द्रभूमि पक्षियों की **128** प्रजातियों का समर्थन करते हैं। यह समुद्री जीवन और घोंसले बनाने वाले समुद्री कछुओं की भी मेजबानी करता है, जो इसे पारिस्थितिक रूप से जीवंत आवास बनाता है।

- **मध्य एशियाई प्लआईवे (CAF):**

- धनुषकोडी **CAF** के साथ यात्रा करने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है। ऐसे पड़ावों का संरक्षण कई लुप्तप्राय और कमजोर पक्षी प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है जो मौसमी आर्द्रभूमि आवासों पर निर्भर हैं।

- **मन्नार की खाड़ी के बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा:**

- यह क्षेत्र यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है, जो इसके वैश्विक पारिस्थितिक महत्व को उजागर करता है। अधिक संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने से वैश्विक जैव विविधता और रामसर कन्वेंशन प्रतिबद्धताओं के साथ भारत का अनुपालन मजबूत होता है।

- **पारिस्थितिकी पर्यटन और आजीविका:**

- सरकार का लक्ष्य स्थायी पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना है, जो स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है और साथ ही लोगों को संरक्षण के बारे में जागरूक कर सकता है।

- **जलवायु लचीलापन:**

- अभयारण्य के मैंग्रोव - विशेष रूप से एविसेनिया और राइज़ोफोरा जैसी प्रजातियाँ - तटीय कटाव और तूफानी लहरों के खिलाफ प्राकृतिक बफर के रूप में काम करती हैं, जो जलवायु अनुकूलन रणनीतियों में योगदान देती हैं।

चुनौतियाँ और विचार

- पर्यटन और पारिस्थितिकी को संतुलित करना: यह सुनिश्चित करना कि पारिस्थितिकी पर्यटन नाजुक आवासों को परेशान न करे, इसके लिए सख्त विनियमन की आवश्यकता होगी।
- स्थानीय भागीदारी: सफलता प्रभावी सामुदायिक भागीदारी और लाभ-साझाकरण मॉडल पर निर्भर करती है।
- निगरानी और प्रवर्तन: अभयारण्य का कई भूमि अधिकार क्षेत्रों में बड़ा क्षेत्र प्रशासनिक और प्रवर्तन चुनौतियों का सामना कर सकता है।

आगे की राह

- अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करना (पर्यावरण, वन, पर्यटन, राजस्व)
- वहन क्षमता आकलन के साथ पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पर्यटन योजनाएँ विकसित करना

- नागरिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जैसे, ईबर्ड, ड्रोन) के माध्यम से पक्षियों की निगरानी बढ़ाना
- जागरूकता अभियान, साइनेज और प्रकृति गाइड के माध्यम से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को शिक्षित करना।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: धनुषकोडी ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं?

1. यह **500** हेक्टेयर में फैला हुआ है।
2. इसमें राजस्व और वन भूमि दोनों क्षेत्र शामिल हैं।
3. यह नीलगिरि पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है।

सही कोड चुनें:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

उत्तर: a)

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारत-मध्य एशिया व्यापार परिषद की बैठक और चौथे भारत-मध्य एशिया संवाद से पहले व्यापार, संपर्क और क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत-मध्य एशिया संबंधों को गहरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह, INSTC और राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार निपटान की रणनीतिक प्रासंगिकता पर जोर दिया।

Jaishankar stresses need to boost India-Central Asia links

More resources are required for that, the External Affairs Minister says, presses for intensifying trade through Chabahar port; he also calls for 'mutual settlement of trade' in national currencies

Kallol Bhattacharjee
NEW DELHI

More efforts and resources need to be invested in improving India's connectivity with Central Asia, External Affairs Minister S. Jaishankar said on Thursday highlighting the need to intensify trade through the Chabahar port in Iran.

At the India-Central Asia Business Council meeting ahead of the fourth India-Central Asia Dialogue scheduled for Friday, Mr. Jaishankar expressed support for "mutual settlement of trade" in national currencies.

"We are discussing this under the Joint Working Group on Chabahar Port under the India-Central Asia platform," said Mr. Jaishankar at the event organised by the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), referring to the requirements to energise the International North South Transport Corridor (INSTC), and greater use of Chabahar port to reduce travel distance and costs between India and Central Asia. Mr. Jaishankar spoke at the event which was also addressed by Murat Nur-



S. Jaishankar and Kazakhstan Deputy Prime Minister Murat Nurtleu signed an MoU to strengthen bilateral ties. @DRSJAISHANKAR/X

tleu, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Kazakhstan; Sirojiddin Muhriddin, Foreign Minister of Tajikistan; Rashid Meredov, Foreign Minister of Turkmenistan; and Saidov Bakhtiyor Odilovich, Foreign Minister of Uzbekistan.

At Friday's dialogue, the Ministers are expected to discuss trade, connectivity, technology, and development cooperation. "They will also share perspectives on challenges to regional security and other regional and global issues of mutual interest," said the Ministry of External Affairs in an announcement regarding the Minister-level meeting. The Foreign Minister-

level dialogue is being seen as significant as it comes a month after India conducted Operation Sindoor against terror targets in Pakistan and reached out to the Taliban administration in Afghanistan.

'Come up with ideas'

Mr. Jaishankar further urged the business chambers to come up with ideas for enhancing bilateral ties between India and Central Asia ahead of a possible India-Central Asia leadership summit that he said could be held "sometime in the not so distant future". In the near future, Prime Minister Narendra Modi is expected to travel for the Shanghai Cooperation Or-

ganization (SCO) meet in Tianjin, China. The first India-Central Asia summit was held in virtual mode on January 27, 2022 when Mr. Modi had hosted the heads of governments of the Central Asian countries. The third meeting of the Foreign Ministers was held during December 18-20, 2021 in New Delhi.

"I would say closer engagements between our banks and financial sector will definitely strengthen our economic interaction. Some beginnings have been made in terms of opening of Special Rupee Vostro Accounts in Indian banks by Central Asian banks and there has also been some discussions about use of UPI [Unified Payment Interface]. I would certainly support that very strongly as also the steps we could take to facilitate mutual settlement of trade in our national currencies," he said.

Mr. Jaishankar said India-Central Asia bilateral trade had touched \$2 billion and added the figure did "not reflect full potential". "The need to address this is today more urgent because of the uncertainties of the international economy," he said.

भारत के लिए मध्य एशिया का सामरिक महत्व

• भू-राजनीतिक प्रासंगिकता:

- मध्य एशिया यूरेशिया के केंद्र में स्थित एक संसाधन-समृद्ध क्षेत्र है। यह प्रमुख शक्तियों-रूस, चीन, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच एक रणनीतिक बफर के रूप में कार्य करता है और क्षेत्रीय स्थिरता और कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

• ऊर्जा और संसाधन:

- यह क्षेत्र विशाल हाइड्रोकार्बन भंडार (विशेष रूप से कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान) से संपन्न है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा विविधीकरण के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

• कनेक्टिविटी चुनौतियाँ:

- पाकिस्तान द्वारा पारगमन से इनकार करने के कारण भारत के पास मध्य एशिया तक सीधी भूमि पहुँच नहीं है। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) और ईरान में चाबहार बंदरगाह जैसे मार्ग मल्टीमॉडल परिवहन के माध्यम से मध्य एशिया तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

• रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में चाबहार बंदरगाह:

- चाबहार भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच प्रदान करता है। भारत-मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह के तहत अपने बुनियादी ढाँचे और संचालन को मज़बूत करना व्यापार और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। • राष्ट्रीय मुद्राओं और यूपीआई का उपयोग:
- राष्ट्रीय मुद्राओं में पारस्परिक व्यापार निपटान और यूपीआई जैसी प्रणालियों के उपयोग के लिए जयशंकर का समर्थन वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के डी-डॉलरीकरण, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और विदेशी मुद्रा निर्भरता को कम करने के प्रयास को दर्शाता है।

• सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता:

- ऑपरेशन सिंदूर और तालिबान तक भारत की पहुँच के बाद संवाद का महत्व और बढ़ गया है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों में भारत की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।

भारत-मध्य एशिया संबंधों के लिए आगे की राह

- मध्य एशियाई सहयोग के साथ **INSTC** और चाबहार बंदरगाह को प्रभावी ढंग से संचालित करना।
- वित्तीय संबंधों का विस्तार करना: बैंकिंग भागीदारी, रुपया वोस्ट्रो खातों और डिजिटल भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देना।
- राजनीतिक गति को बनाए रखने के लिए नियमित नेतृत्व शिखर सम्मेलन आयोजित करना।
- नवीकरणीय और हाइड्रोकार्बन में ऊर्जा भागीदारी और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना।
- आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और विकास पर समन्वित कार्रवाई के लिए एससीओ और भारत-मध्य एशिया वार्ता जैसे बहुपक्षीय मंचों का लाभ उठाना।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: मध्य एशिया के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों के अभिसरण से प्रेरित है। भारत-मध्य एशिया संबंधों को मजबूत करने में चाबहार बंदरगाह और INSTC जैसी कनेक्टिविटी पहलों की भूमिका और इसमें शामिल चुनौतियों पर चर्चा करें। (250 Words)

Page 07 : GS 2 and 3 : Social Justice : Issues relating to health and Science and Technology

भारत में कोविड-19 के मामलों में मामूली वृद्धि देखी जा रही है, जो NB.1.8.1 और LF.7 जैसे ओमिक्रॉन सब-वेरिएंट के कारण है। जबकि अधिकांश मामले फ्लू जैसे लक्षणों के साथ हल्के बने हुए हैं, वैक्सीन की तैयारी, बूस्टर खुराक की आवश्यकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों को लेकर बहस फिर से शुरू हो गई है। विशेषज्ञों और ICMR जैसे संस्थानों ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण की आवश्यकता पर जोर दिया है, लेकिन विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है।



Taking care: People wearing masks near a hospital in Visakhapatnam on May 30, 2022. Doctors said that at present everyone should focus on personal protection. K.A. DEEPAK

Taking stock of COVID-19 vaccines

As cases rise in India, doctors across the board say that, at present, they see no need for a mass-vaccination drive; the ICMR has maintained that the new cases have mostly been mild with reported symptoms akin to those of the common cold or seasonal flu; experts stress on the need to practice personal hygiene

The Hindu Bureau

Over the past few weeks, headlines around India and Southeast Asia have centred around a virus that the world has wanted to forget: COVID-19. At first, an uptick in cases in Hong Kong, Singapore and other parts of the region caused concern. Gradually though, India too, witnessed a surge in cases, with numbers as of Thursday standing at 4,866, and fatalities at 51.

Doctors and experts have said time and again that there is no reason to panic – spikes and dips in COVID-19 cases are expected, the virus they say, is co-circulating with other seasonal infections and no major waves are expected. Misinformation, in fact, is harder to battle, they point out.

Residents however, are raising questions about the COVID-19 vaccines: it may be recalled that India launched the world's largest COVID-19 immunisation drive in January 2021. To date, over 220 crore doses of vaccines have been administered in the country as per the Co-WIN dashboard. These were primarily of the two vaccines available then, AstraZeneca's Covishield and Bharat Biotech's Covaxin.

What is the vaccine situation now? Rajiv Balli, Director General of the Indian Council of Medical Research (ICMR), the country's nodal scientific body, has said there is absolutely no need to initiate mass booster doses for COVID-19 vaccination at present, and neither is there a direction from the Central government for this.

Speaking about the rising number of cases in India, Dr. Balli, however, noted that individual doctors could recommend booster doses to patients on a case-to-case basis, depending on the needs of individuals.

He further explained that the need for mass vaccination, while not felt at present, could arise, with perhaps a mutation in the virus or its spread. "For that, India already has the capacity to scale up production and provide for the general public. We have done this before and there is no need to panic," he said, reiterating that as of now there was no need for individuals to rush in to get a booster dose.

Since vaccines used in 2021 and 2022 have now fallen into disuse and expired,

there are no stocks at present, a government official said, adding that the government could direct manufacturers to produce more stocks when necessary. Most States, including Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and West Bengal, have no stocks of the vaccine at present.

Variants driving the spike

As of now, the variants of COVID-19 doing the rounds in India are descendants of the Omicron variant, first reported in November 2021. The emerging sub-variants – NB.1.8.1 and LF.7 – that are driving the current COVID surge are descendants of JN.1, a sub-lineage of the Omicron BA.2.86 variant.

In Kerala, for instance, a senior Health Department official said, "Almost all of the samples sent for whole-genome sequencing from the State have shown that the circulating virus variant is LF.1, one of the descendants of Omicron, the immune evasiveness of which is quite well known." These sub-variants, doctors say, are, so far, causing mild illnesses.

P. Senthur Nambi, senior consultant, Infectious Diseases, Apollo Hospitals, Chennai, said that most of the COVID-19 patients he had seen so far have done well. "Most of them had only an upper respiratory infection. Gone are the days when COVID-19 affected the lungs causing pneumonia and breathing difficulties. These patients were managed based on their symptoms and most of them did not require any COVID-specific antiviral medications. Prior exposure to the infection, the effects of the vaccines taken or a combination of both factors with vaccine-induced antibodies could be playing a protective role," he explained.

Cases this time around have mostly been mild, the ICMR has maintained, with reported symptoms akin to those of the common cold or seasonal flu. "The key difference with these new strains," said Sujana Bardhan, consultant (TB & chest diseases), Narayana Hospital, RN Tagore Hospital, Kolkata, "is their speed, not their severity. Hospitals are well-prepared and the healthcare system remains under no immediate strain. Nonetheless, the importance of basic preventive measures cannot be overstated."

Are vaccines needed at present?

Doctors across the board say that at present, they see no need for a mass-vaccination drive.

"By the time Omicron ran its course, almost all of our population had been exposed to the virus. Even when the antibody protection wanes, the long-term

immune memory remains. This innate immunity plus the vaccine-derived immunity through good coverage of the initial two doses means that most people have strong hybrid immunity against COVID-19," a Kerala Health Department official said, adding that the previous vaccines may not even be very effective against the Omicron variants – they would, however, offer protection against serious forms of the disease.

Though two indigenously developed nasal vaccines specifically targeting Omicron variant from Bharat Biotech and Indian Immunologicals as well as another indigenous mRNA vaccine for the same variant were made available in the Indian market, the uptake was low, doctors said. Kiran Madala, a Hyderabad-based doctor, part of an international group of genetic epidemiologists under the COVID Treatment Exchange Organisation, said the current World Health Organization guidelines recommend vaccines primarily for individuals above the age of 70 to 80; those who are immunocompromised; and patients with multiple comorbidities. Children, especially those aged two to six, do not need vaccination unless they have underlying health issues or are immunosuppressed.

Dr. Nambhi in Chennai said some patients, those who have travel obligations, have requested the vaccines, but none are available at present. "But I wish that there was an option of vaccination, not for the general population in large but for two subsets of patient groups in whom the infection could cause problems," he said. The first group of patients are those who have not received any COVID-19 vaccine due to various factors and had no COVID-19 infection in the past. So, they will neither have natural immunity or vaccine-induced immunity. Though a weakened virus, it could cause complications such as pneumonia leading to hospitalisation, especially if they are over 65 years of age, he said. The second subset of patients are those with underlying comorbidities such as heart ailments, Chronic Obstructive Pulmonary Disease with poor lung function and immune-compromised persons, including those who have undergone organ transplants. "Other coronaviruses such as the Middle East Respiratory Syndrome did not last long, but we are still talking about COVID since the end of 2019. So, a vaccine will be beneficial for these two groups of persons

in the long run from the public health perspective. But this being a mutating virus, we will need to modify the vaccines on a regular basis," Dr. Nambhi observed.

T. Jacob John, retired professor of clinical virology at Christian Medical College, Vellore, also said that the elderly and immunocompromised people needed to be vaccinated again, irrespective of whether they were fully vaccinated (two doses and a booster) or had been exposed to the virus earlier. "These people are vulnerable even with mild

variants as their immune systems are weak, and they are at greater risk of complications."

State governments, however, have taken a more cautious stance. "Whether vaccination is required or not depends on many factors," said T. S. Selvarajagopal, T.N. Director of Public Health and Preventive Medicine. "We need to study the epidemiology of the current cases before commenting on the requirement for vaccination now," Kerala has said it was "not advocating for or against COVID booster shots" because of the lack of epidemiological data that booster doses offered enhanced protection against emerging immune-evasive variants.

What next? The Delhi High Court, earlier, directed the Centre to submit a thorough status report detailing its actions regarding the policy for sample collection, collection centres, and transportation of samples. It also stressed urgency to finalise Standard Operating Procedures.

While preparedness of health systems remains crucial, doctors said that at present everyone should focus on personal protection, with special care being given to vulnerable sections of the population. As the virus continues to adapt, so must we, Dr. Bardhan said. Staying informed and following trusted health sources, personal protection and hygiene measures, avoiding crowded places when possible or masking up, refraining from going outdoors when ill and maintaining a healthy, well-balanced lifestyle could help navigate this phase and any more to come.

(Compiled by Zubeida Hamid with inputs from C. Mayu in Kerala, Serena Josephine M. in Chennai, Rinda Shajon Prappadan in Delhi, Afshan Yaseem in Bengaluru, Shrabana Chatterjee in Kolkata and Siddharth Kumar Singh in Hyderabad.) (health@thehindu.co.in)

THE GIST

Doctors say spikes and dips in COVID-19 cases are expected; the virus they say, is co-circulating with other seasonal infections and no major waves are expected. Misinformation, in fact, is harder to battle, they point out

As of now, the variants of COVID-19 doing the rounds in India are descendants of the Omicron variant, first reported in November 2021. The emerging sub-variants – NB.1.8.1 and LF.7 – that are driving the current COVID surge are descendants of JN.1, a sub-lineage of the Omicron BA.2.86 variant

While preparedness of health systems remains crucial, doctors said that at present everyone should focus on personal protection, with special care being given to vulnerable sections of the population, including elderly citizens, young children, pregnant women and those with immune-compromised systems or chronic illnesses

For feedback and suggestions For 'Science', please write to science@thehindu.co.in with the subject 'Daily page'

मुख्य मुद्दे और विश्लेषण

• सामूहिक टीकाकरण की तत्काल आवश्यकता नहीं

- **ICMR** और प्रमुख विशेषज्ञों ने पिछले संपर्क और प्राथमिक टीकाकरण कवरेज के कारण हल्के लक्षणों और उच्च प्राकृतिक प्रतिरक्षा स्तरों का हवाला देते हुए राष्ट्रव्यापी बूस्टर खुराक की आवश्यकता को खारिज कर दिया है।
- भारत ने महामारी के चरम के दौरान **220** करोड़ से अधिक खुराकें दी, जिससे अधिकांश आबादी में हाइब्रिड प्रतिरक्षा (प्राकृतिक + वैक्सीन-प्रेरित) पैदा हुई।

• सीमित वैक्सीन उपलब्धता

- पहले के अभियानों (कोविशील्ड, कोवैक्सिन) के अधिकांश टीके समाप्त हो चुके हैं।
- ओमिक्रॉन वेरिएंट (नाक, **mRNA**) के लिए तैयार किए गए नए टीके उपलब्ध हैं, लेकिन उनका कम उपयोग किया जाता है और सरकारी स्टॉक वर्तमान में मौजूद नहीं है।

• नए COVID वेरिएंट - कम गंभीर लेकिन तेजी से फैलने वाले

- वर्तमान उछाल ओमिक्रॉन उप-वंश, विशेष रूप से **LF.7** और **NB.1.8.1** के कारण है।
- विशेषज्ञों ने ध्यान दिया कि ये वेरिएंट उच्च संक्रामकता लेकिन कम विषाणु दिखाते हैं, जो ज्यादातर ऊपरी श्वसन संबंधी लक्षण पैदा करते हैं।

• उच्च जोखिम वाले समूहों पर ध्यान दें

- **WHO** और भारतीय विशेषज्ञ निम्नलिखित के लिए चयनात्मक टीकाकरण की सलाह देते हैं:

- बुजुर्ग (**70-80+** वर्ष)
- प्रतिरक्षाविहीन व्यक्ति
- सह-रुग्णता वाले लोग (हृदय, फेफड़े, प्रत्यारोपण मामले)
- गलत सूचना और सार्वजनिक जागरूकता

- जबकि वायरस लगातार उत्परिवर्तित हो रहा है, गलत सूचना और घबराहट सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अधिक गंभीर चुनौतियाँ पेश कर रही हैं।
- विशेषज्ञ सरकार से पारदर्शी संचार बनाए रखने, अद्यतन दिशा-निर्देश प्रकाशित करने और वैक्सीन से संबंधित मिथकों से निपटने का आग्रह करते हैं।

• तैयारी और भविष्य की योजना

- राज्य सरकारें सतर्क हैं, वैक्सीन नीति पर निर्णय लेने से पहले महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययनों की प्रतीक्षा कर रही हैं।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से निगरानी, नमूना संग्रह और रोकथाम रणनीतियों पर एसओपी और स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

- डॉक्टरों का सुझाव है कि अब ध्यान व्यक्तिगत सुरक्षा पर होना चाहिए, न कि घबराहट पर - जिसमें भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना, स्वच्छता और शुरुआती लक्षणों का प्रबंधन शामिल है।

आगे की राह

- उभरते हुए वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए प्रहरी निगरानी और जीनोमिक अनुक्रमण को मजबूत करना।
- गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए सार्वजनिक संचार रणनीतियों को बनाए रखना।
- आपातकालीन उपयोग के लिए वैक्सीन का भंडार तैयार करना, विशेष रूप से कमज़ोर आबादी के लिए।
- ज़रूरत पड़ने पर लचीले रोलआउट के लिए **Co-WIN** जैसे डिजिटल टूल को बढ़ाना।
- भविष्य में श्वसन संबंधी बीमारी के प्रकोप से निपटने के लिए व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में **COVID** प्रतिक्रिया को एकीकृत करना।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: कोविड-19 के हल्के रूप में फिर से उभरने के साथ, भारत को अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की नई परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। नए वेरिएंट के मद्देनजर लक्षित टीकाकरण और तैयारियों की वर्तमान रणनीति की आलोचनात्मक जांच करें। सावधानी और सामान्य स्थिति के बीच संतुलन बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (250 words)

भारत सरकार ने घोषणा की है कि अगली दशकीय जनगणना अपने निर्धारित समय (2021) से छह साल बाद 1 मार्च, 2027 तक पूरी हो जाएगी। शुरू में कोविड-19 के कारण हुई देरी को अब राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जा रहा है, खासकर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और प्रस्तावित जाति गणना से जुड़े होने के कारण। जबकि डेटा संग्रह के लिए डिजिटल उपकरणों को अपनाने का स्वागत किया जा रहा है, देरी के पीछे के समय और इरादे ने विद्वानों, नागरिक समाज और कुछ क्षेत्रीय सरकारों के बीच चिंता पैदा कर दी है।

मुख्य मुद्दे और विश्लेषण

• देरी और इसके परिणाम

- 2021 के लिए निर्धारित जनगणना अब 2027 तक के लिए स्थगित कर दी गई है - भारत के इतिहास में सबसे लंबा अंतराल।
- अद्यतन जनसंख्या डेटा की अनुपस्थिति प्रभावित करती है:

- कल्याणकारी योजनाओं का लक्ष्यीकरण
- राज्यों को संसाधन आवंटन
- शहरी नियोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा का बुनियादी ढांचा

- देरी साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को कमजोर करती है और सबसे गंभीर रूप से कमजोर आबादी को प्रभावित करती है।

• डिजिटल जनगणना: एक दोधारी तलवार

- पहली बार, जनगणना डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी, जो वादा करती है:

- तेज़ डेटा प्रोसेसिंग
- अधिक पहुँच और विश्लेषणात्मक मूल्य

- हालाँकि, यह निम्नलिखित के बारे में गंभीर चिंताएँ भी पैदा करता है:

- डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा
- सीमित पहुँच वाले ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल बहिष्कार
- जाति गणना - वरदान या जोखिम?

- 1931 के बाद पहली बार, जाति-आधारित डेटा एकत्र किया जा सकता है।

Injustice in the delay

The announcement of the Census is welcome, but the delay is unjust

India's next decadal population census, initially delayed by the COVID-19 pandemic, is now scheduled to conclude by March 2027, after a further delay apparently fuelled by political motivations. The Census in 2021 did not take place as planned, thus impacting different aspects of governance, especially social security schemes for vulnerable populations that rely heavily on updated demographic data for effective and efficient delivery. For the first time, the Census will be digitally administered, enabling faster data gathering and easier accessibility for analysis, thereby allowing population-level data to be more dynamic. However, this technological adoption also heightens concerns regarding data theft and privacy. While the nature of the Census will evolve, transparency at all levels will be crucial to building public trust in the exercise. Preparations for this massive operation, which will reach every household, are underway, with more logistical details anticipated in the weeks ahead.

India stands at a demographic crossroads, facing the challenges of growing populations of the young and the old alongside significant regional variations in key indicators. Fresh data from the Census can help address many issues. For the first time since 1931, caste categories will be enumerated. While more reliable data on the socio-economic standing of caste groups can inform development planning, the potential for further social segmentation makes caste enumeration a double-edged sword. A critical aspect of the upcoming Census is its link to the next delimitation of Lok Sabha and Assembly constituencies, which will redraw India's electoral map. The Constitution mandates that the next inter-State delimitation be based on population figures from the first Census after 2026. The current distribution of Lok Sabha seats is based on the 1971 population spread. With the reference date for the Census set as March 1, 2027, for most of the country, this can pave the way for the next delimitation exercise. States that have experienced lower population growth in recent decades, particularly in the peninsular region, have expressed concern that their parliamentary representation will diminish if population becomes the sole criterion for redistribution. The Centre has yet to clarify its stance on this matter. With the Census now in motion, it is imperative for the Centre to engage with all stakeholders and build consensus on the sensitive issue of delimitation. Otherwise, the delay in the announcement of the Census will be taken to mean as an attempt to ensure that the ruling BJP benefits from the increased representation for the Hindi-speaking States.

○ सकारात्मक:

- सामाजिक-आर्थिक असमानताओं की बेहतर समझ
- सकारात्मक कार्रवाई का बेहतर लक्ष्यीकरण

○ जोखिम:

- जातिगत पहचान को मजबूत कर सकता है
- राजनीतिक आख्यानों को ध्रुवीकृत कर सकता है और सामाजिक विभाजन को गहरा कर सकता है
- जनगणना-परिसीमन लिंक और संघीय तनाव
 - संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, परिसीमन 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर होगा।
 - वर्तमान सीट वितरण 1971 के आंकड़ों पर आधारित है, जो जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के बावजूद प्रतिनिधित्व को स्थिर रखता है।
 - दक्षिणी राज्य, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है, संसद में प्रतिनिधित्व खोने का डर है यदि सीटों की संख्या को सख्ती से जनसंख्या से जोड़ा जाता है।
- विश्वास की कमी और राजनीतिक धारणा
 - जनसंख्या-आधारित मानदंडों को समानता संबंधी चिंताओं के साथ कैसे संतुलित किया जाएगा, इस पर केंद्र की चुप्पी अटकलों को बढ़ाती है।
 - आलोचकों का तर्क है कि देरी से सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा हो सकता है, खासकर हिंदी भाषी राज्यों में, जो भविष्य के परिसीमन में सीटें हासिल कर सकते हैं।

आगे की राह

- जनगणना की योजना और क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- व्यापक परामर्श के माध्यम से परिसीमन मानदंडों पर केंद्र के रुख को स्पष्ट करना।
- डिजिटल जनगणना के लिए डेटा गोपनीयता कानून और तकनीकी सुरक्षा उपाय लागू करना।
- ऐसी नीतियाँ बनाना जो जनसंख्या समानता और शासन दक्षता के बीच संतुलन को दर्शाती हों।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत की दशकीय जनगणना के आयोजन में बार-बार होने वाली देरी का असर डेटा संग्रह से परे भी पड़ता है - सामाजिक कल्याण से लेकर चुनावी प्रतिनिधित्व तक। 2027 की जनगणना के स्थगन और प्रस्तावित डिजिटल स्वरूप से उत्पन्न होने वाली शासन व्यवस्था और संघीय चिंताओं की आलोचनात्मक जांच करें। (250 words)

Page : 08 Editorial Analysis

A Eurocentric reset, a gateway for India

In a diplomatic move, with far-reaching consequences, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer's new agreement with the European Union (EU) signals a powerful "reset" of their relations, resuming cooperation on food standards, fishing rights, defence and border checks. While this development may appear Eurocentric, it opens a gateway to possibilities and challenges for India that demand urgent attention.

The U.K. and the EU are among India's most important trade and diplomatic partners, and their renewed alignment could redraw India's global strategy map. For Indian exporters, this could simplify compliance and revive supply chain fluidity. For policymakers, this presents an opportunity to strengthen strategic alliances. For the diaspora, this could reshape education and migration prospects. In short, the U.K.-EU reset is not just a regional recalibration. It is a moment that could redefine India's trade corridors, diplomatic engagements, and soft power leverage in the West.

A reshaping of India's export dynamics

The renewed collaboration in areas such as food safety, customs coordination and fisheries is poised to significantly influence Indian exports to both regions. In FY2024, India's exports to the EU stood at \$86 billion, while exports to the U.K. totalled \$12 billion, highlighting their strategic role in India's external trade.

Post-Brexit, Indian exporters have grappled with navigating two separate regulatory regimes, especially in key sectors such as pharmaceuticals, textiles, seafood, and agro-based products. A harmonised U.K.-EU regulatory framework could simplify compliance, reduce redundancy and lower operational costs. India, a significant



Vipin Benny

is Assistant Professor and Research Supervisor, St. Thomas College (Autonomous), Thrissur, Kerala, and the author of 'The Scenario of Economic Innovations in India: An Idea for Inventor' (2021) and 'Elevating Excellence: The Relevance of Internal Marketing in Higher Education Institutions in India' (2023)

The U.K.-EU reset has the potential to redefine India's trade, diplomatic engagements and soft power leverage in the West

supplier of generic medicines to the U.K., fulfilling over 25% of its pharmaceutical needs, would benefit from a unified approval mechanism that accelerates clearances and enhances cost efficiency.

Similarly, Indian seafood exports, valued at ₹60,523.89 crore (approximately \$7.38 billion) in FY2024, could face fewer trade barriers if the food standards and fishing policies are aligned. However, tighter common standards might challenge Indian Small and Medium Enterprises, which often lack the capital and technical know-how. To remain competitive, India must strengthen its export ecosystem through initiatives such as the Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) and the Production-Linked Incentive (PLI) scheme.

A stronger voice in global diplomacy

Beyond trade, the geopolitical dimensions are significant for India. A more synchronised U.K.-EU foreign policy, particularly in defence and the Indo-Pacific, offers India an avenue to enhance its multilateral coordination with the EU. India already operates under the EU-India Strategic Partnership: A Roadmap to 2025, and in 2022, it renewed its Comprehensive Strategic Partnership with the U.K., covering cyber security, climate action, and maritime security.

As the U.K. realigns its policies with the EU, India could benefit from cohesive western support on global platforms, such as the United Nations, the G-20, and the World Trade Organization (WTO). Strategic ties with France, Germany and the U.K. are vital to India's defence modernisation and technological ambitions, especially regarding naval power.

Notably, India-France bilateral trade reached \$15.1 billion in 2024-25; landmark defence

agreements with Germany and the U.K. have focused on technology transfer and joint development. A coordinated U.K.-EU defence policy could open doors for deeper trilateral or multilateral engagements in the Indo-Pacific, where shared concerns over China's assertiveness persist.

Additionally, India's leadership in the Global South – spotlighted during its G-20 presidency in 2023 – can be amplified by leveraging the U.K.-EU thaw to drive collective action on climate finance, digital infrastructure and global governance reforms. A unified West could become a more dependable ally for India if it engages with India, strategically and assertively, in the future

Enhancing trade and talent power

On the mobility front, India has the world's largest diaspora, which includes large communities in the U.K. and across the EU. In 2024, the U.K. issued more than 1,10,000 student visas to Indian nationals, placing India among the top sources of international students.

While post-Brexit restrictions limited access for Indian professionals to EU markets, renewed U.K.-EU border coordination could enable partial mobility, creating a semi-integrated talent corridor. This could also bolster India's migration pacts with Germany, France and Portugal by embedding them within a broader U.K.-EU framework.

These converging shifts – trade liberalisation, mobility reintegration, and foreign policy alignment – present rare diplomatic and economic opportunities. To seize these opportunities, India must accelerate reforms, modernise its export infrastructure, and assert its role in global governance.

Paper 02 : अंतरराष्ट्रीय संबंध

UPSC Mains Practice Question : यू.के.-ई.यू. कूटनीतिक पुनर्निर्धारण भारत के लिए अपनी रणनीतिक, आर्थिक और प्रवासन नीतियों को पुनः निर्धारित करने का एक दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करता है। इस घटनाक्रम के आलोक में भारत के लिए संभावित लाभों और चुनौतियों की जांच करें। (250 words)

संदर्भ:

- ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में हाल ही में यू.के.-ई.यू. का पुनर्गठन ब्रेक्सिट के बाद की भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मोड़ दर्शाता है। हालाँकि यह कदम यूरोकेंद्रित प्रतीत होता है, लेकिन यह भारत की विदेश नीति, व्यापार, प्रवासी गतिशीलता और रणनीतिक गठबंधनों के लिए व्यापक निहितार्थ रखता है। यू.के. और ई.यू. दोनों ही भारत के प्रमुख व्यापार और कूटनीतिक साझेदारों में से हैं, इसलिए उनका नया संरेखण भारत की बाहरी जुड़ाव रणनीति को नया आकार दे सकता है।

मुख्य आयाम और विश्लेषण

- **व्यापार और निर्यात गतिशीलता**
- खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क आदि पर यू.के.-ई.यू. सामंजस्य, भारतीय निर्यात को सुव्यवस्थित कर सकता है।
- भारतीय निर्यातक वर्तमान में दो विनियामक ढाँचों का उपयोग करते हैं; एक एकीकृत व्यवस्था निम्न कर सकती है:
 - अनुपालन लागत कम करना
 - उत्पाद अनुमोदन में तेजी लाना (विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, समुद्री भोजन)
- चुनौती: सख्त सामान्य मानक संसाधनों और प्रौद्योगिकी की कमी वाले एस.एम.ई. को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- अवसर: भारत प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए RoDTEP, PLI और निर्यात अवसंरचना उन्नयन जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकता है।

रणनीतिक और कूटनीतिक संभावनाएँ

- यू.के. और यूरोपीय संघ के बीच तालमेल से निम्नलिखित परिणाम मिल सकते हैं:
 - जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा पर भारत के साथ बेहतर समन्वय
 - इंडो-पैसिफिक सहयोग में बढ़ी हुई उपस्थिति, विशेष रूप से फ्रांस और जर्मनी के साथ
- **जैसे मंचों में बहुपक्षीय समन्वय की संभावना:**
 - G20, UN, WTO, क्लाइमेट्स और क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन
 - यू.के.-यू.ई. के बीच संबंधों में सुधार भारत को जलवायु वित्त, वैश्विक शासन और डिजिटल इक्विटी में वैश्विक दक्षिण सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक कूटनीतिक वजन प्रदान करता है।

प्रवासी और गतिशीलता एकीकरण

- भारत दोनों क्षेत्रों में छात्रों और कुशल प्रवासियों का एक शीर्ष स्रोत है।
- ब्रेक्सिट के बाद, यू.के. से यूरोपीय संघ में गतिशीलता प्रतिबंधित थी; पुनः एकीकरण प्रस्ताव:
 - भारत, यू.के. और यूरोपीय संघ के बीच प्रतिभा गलियारा
 - प्रवास साझेदारी (जर्मनी, पुर्तगाल, फ्रांस) के लिए बढ़ी हुई संभावना
- छात्र वीजा जारी करना, द्विपक्षीय शिक्षा समझौते और सांस्कृतिक संबंधों को और गति मिल सकती है।

भारत के लिए आगे का रास्ता

- भविष्य के यू.के.-यू.ई. मानदंडों के अनुपालन के लिए निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत करना।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त रक्षा विकास सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी का लाभ उठाना।
- द्विपक्षीय ढांचे के भीतर प्रवास नीतियों को एकीकृत करने के लिए प्रवासी कूटनीति का निर्माण करना।
- वैश्विक शासन में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए इस अवसर का उपयोग करके जी20 जैसे मंचों में नेतृत्व का दावा करना।
- सुनिश्चित करना कि भविष्य के यू.के.-यू.ई. आर्थिक और रणनीतिक संवादों में भारत के हितों का सक्रिय रूप से प्रतिनिधित्व किया जाए।